

इससे पहले: एन. के. सोधी, जे.

मेसर्स के. के. कक्कड़ और एसोसिएट,-

याचिकाकर्ता।

बनाम

आय कर आयुक्त और अन्य,-

उत्तरदाता।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 138021

5 सितंबर, 1991

आयकर अधिनियम, 1961-एस.एस. 142(1), 144' 184, 185, 185(5), 186-बेस्ट जजमेंट असेसमेंट-फर्म, अनुभाग के तहत 1977 में पंजीकृत 184 और 185-इसके बाद निर्धारिती फर्म को पंजीकृत फर्म माना जाएगा चूंकि फॉर्म 12 में रिटर्न नियमित रूप से जमा किया गया था-दाखिल करने में विफलता विशेष मूल्यांकन वर्ष के लिए रिटर्न-धारा 142(1) के तहत नोटिस जारी किया गया - जवाब देने में विफलता - निर्धारिती ने एकपक्षीय कार्रवाई की धारा 144 और सर्वोत्तम निर्णय पर किया गया मूल्यांकन-आईटीओ उद्देश्य-टेडली धारा 185(5) के तहत कार्य करते हुए मूल्यांकन स्थिति प्रदान करने में विफल रहे पंजीकृत फर्म - ऐसी स्थिति से इनकार अवैध है - आईटीओ रद्द नहीं कर सकता निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना निर्धारिती का पंजीकरण धारा 186(2).

(पैरा 4 और 5)

माना गया कि चूंकि फॉर्म 12 समय पर जमा किया गया था, इसलिए प्रावधान-अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (7) के तहत इसे अनिवार्य बना दिया गया कि पूर्व वर्षों में दिया गया पंजीकरण जारी रहेगा उस वर्ष भी प्रभाव पड़ेगा.

यह अभिनिर्धारित किया गया कि तत्काल मामले में, फर्म को वर्ष में पहली बार पंजीकृत किया गया था और इसके बाद इसका पंजीकरण जारी रहा और संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए फर्म द्वारा समय पर अपेक्षित घोषणा प्रपत्र 12 प्रस्तुत किए जाने के बाद, आयकर अधिकारी उस मूल्यांकन वर्ष के लिए अधिनियम की खंड 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन करते हुए, इसलिए अधिनियम की खंड 186 (2) का सहारा लिए बिना पंजीकरण को रद्द नहीं कर सकते। आयकर का विवादित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और रद्द किए जाने के योग्य है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि:-

1. 19 मार्च, 1987 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पंजीकरण से इनकार करते हुए पारित आदेश और 8 जून, 1989 को आयकर आयुक्त, रोहतक द्वारा इसे बरकरार रखते हुए और संशोधन याचिका को खारिज करते हुए पारित आदेश को रद्द करते हुए मामले के अभिलेखों को तलब किया जाए और सरशियोरैराई की प्रकृति में एक रिट या निर्देश दिया जाए:
2. कोई अन्य रिट या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, पारित किया जाए।
3. आदेशों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करना 'पी-के' से 'पी-3' के अनुलग्नक को समाप्त किया जाना चाहिए; और
4. रिट याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बी. के. झिंगन।

प्रतिवादी की ओर से ए.के.मित्तल, अधिवक्ता।

## न्याय

एन. के. सोधी, जे.

1. मेसर्स के. के. कक्कड़ एंड एसोसिएट्स एक साझेदारी फर्म (जिसे इसके बाद 'द फर्म' कहा जाता है) के रूप में फरीदाबाद में अपनी गतिविधियों को चलाने वाले ठेकेदारों

की एक फर्म है। यह पुराना है। और आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत नियमित निर्धारित और अधिनियम की खंड 184 और 185 के तहत पहली बार निर्धारण वर्ष के लिए एक फर्म के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया था और उसके बाद अधिनियम की खंड 184 की उप-खंड (7) के तहत एक पंजीकृत फर्म के रूप में माना जा रहा था क्योंकि आयकर नियमों के नियम 24 द्वारा परिकल्पित फॉर्म-12 उसकी ओर से प्रस्तुत किया जा रहा था। मूल्यांकन वर्ष 1984-85 के लिए, जो अब विचाराधीन वर्ष है, फर्म ने समय पर फॉर्म-12 में सामान्य घोषणा दायर की और इसलिए, फर्म को पहले से दिए गए पंजीकरण का प्रभाव इस मूल्यांकन वर्ष में भी जारी रखना पड़ा। अधिनियम की खंड 184 की उप-खंड (7) के प्रावधानों को देखते हुए आयकर अधिकारी द्वारा पंजीकरण का कोई नया आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि फर्म के गठन या भागीदारों के शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण कार्यवाही के दौरान, अधिनियम की खंड 139 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की वापसी के लिए कहा गया था, जिसके जवाब में फर्म ने कोई विवरणी दाखिल नहीं की थी। फिर से, अधिनियम की खंड 142 (1) के तहत नोटिस जारी किए गए थे जो फर्म को विधिवत दिए गए थे लेकिन इन दोनों का पालन नहीं किया गया था। आयकर अधिकारी के पास पिछले रिकॉर्ड के आधार पर अधिनियम की खंड 144 के तहत एकतरफा मूल्यांकन पूरा करने के एकपक्षीय कोई विकल्प नहीं बचा था। अधिनियम की खंड 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ते हुए, आयकर अधिकारी ने अधिनियम की खंड 185 (5) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्धारण वर्ष के लिए फर्म को पंजीकरण देने से इनकार कर दिया और आयकर अधिकारी इस आधार पर आगे बढ़े कि फर्म का दर्जा एक अपंजीकृत फर्म का था। इस संबंध में आयकर अधिकारी द्वारा 19 मार्च, 1987 को पारित आदेश की एक प्रति रिट याचिका के साथ संलग्नक पीएल है। इस आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की खंड 264 के तहत आयकर आयुक्त की शक्तियों का आह्वान किया, जिन्होंने 8 जून, 1989 के अपने आदेश (रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी4) के माध्यम से - पुनरीक्षण याचिका में कहा गया है कि चूंकि फर्म अधिनियम की धारा 139 (2) और 142 (1) के तहत जारी किए गए नोटिसों का पालन करने में विफल रही है, इसलिए आयकर अधिकारी ने फर्म का पंजीकरण जारी रखने से इनकार कर दिया। इस दृष्टिकोण के लिए, आयुक्त ने *सी. एल. में रिपोर्ट किए गए कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। टी. वी. सोयाज-मुल नागरमुल* <sup>1</sup>(1)। याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में आयकर अधिकारी के आदेश के साथ-साथ आयुक्त के आदेश को भी चुनौती दी है।

---

(1) 139 I.T.R. 239

2. फर्म की ओर से एकमात्र तर्क यही है, चूंकि फॉर्म-12 आयकर अधिकारी को समय पर जमा कर दिया गया था। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष बनाते समय वह ऐसा नहीं कर सके, सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन फर्म को पंजीकृत मानने से इंकार करता है। फर्म और यदि वह पंजीकरण रद्द करने के लिए इच्छुक है, तो वह की धारा 186 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, कार्यवाही करना। उत्तरदाताओं ने रिट के रुख का खंडन किया है। याचिकाकर्ता और आक्षेपित आदेशों को उचित ठहराने की मांग की गई है, की धारा 185 की उपधारा 5 के प्रावधानों का आधार कार्यवाही करना। उत्तरदाताओं का मामला यह है कि आयकर के बाद से। अधिकारी को धारा 144 के तहत एक पक्षीय मूल्यांकन पूरा करना था। अधिनियम के अनुसार, फर्म को पंजीकरण से इंकार करना परिणामी था, ऐसे मूल्यांकन आदेश का निर्माण।

3. पक्षकारों के बीच विवाद को समझने के लिए, अधिनियम की आदेश 184, 185 और 186 के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करना आवश्यक है जो संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“धारा 184. पंजीकरण के लिए आवेदन.

- (1) XX XX XX XX XXX
- (2) XX XX XX XX XXX
- (3) XX XX XX XX XXX
- (4) XX XX XX XX XXX
- (5) XX XX XX XX XXX
- (6) XX XX XX XX XXX
- (7) XX XX XX XX XXX

7. जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी फर्म को पंजीकरण दिया जाता है, वहां यह प्रत्येक बाद के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावी होगा:

बशर्ते कि:

- (i) फर्म के संविधान या भागीदारों के शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि लिखत द्वारा प्रमाणित किया गया है, साझेदारी जिसके आधार पर पंजीकरण दिया गया था; और
- (ii) फर्म, खंड 139 (चाहे मूल रूप से निर्धारित हो या विस्तार पर) की उप-खंड (1) या उप-खंड (2) के तहत अनुमत समय की समाप्ति से पहले, निर्धारित प्रपत्र में उस प्रभाव की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए एक घोषणा प्रस्तुत करती है और निर्धारित तरीके से सत्यापित होती है, इसलिए, जहां आयकर अधिकारी का समाधान हो जाता है कि फर्म को इस तरह से अनुमत समय के भीतर घोषणा प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, वह निर्धारण किए जाने से पहले किसी भी समय घोषणा प्रस्तुत करने के लिए फर्म को अनुमति दे सकता है।

(8) X X X X X X X X

(1) X X X X X X X X

(2) X X X X X X X X

(3) X X X X X X X X

(4) X X X X X X X X

खंड 185। आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

(5) इस खंड में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी भी मूल्यांकन वर्ष के संबंध में, भाग पर है, किसी फर्म की, ऐसी कोई विफलता जैसा कि धारा 144 में उल्लिखित है, आयकर अधिकारी फर्म को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है, मूल्यांकन वर्ष.

खंड 186। पंजीकरण रद्द करना।

(1) X X X X X X X X

(2) यदि, जहां कोई फर्म किसी निर्धारण वर्ष के लिए खंड 184 की उप-खंड (7) के तहत पंजीकृत की गई है या उसका पंजीकरण प्रभावी है, तो फर्म की ओर से, निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसी कोई विफलता है जैसा कि खंड 144 में उल्लेख किया गया है, तो आयकर अधिकारी निर्धारण वर्ष के लिए फर्म का पंजीकरण रद्द कर सकता है, फर्म

को उसके पंजीकरण को रद्द करने के अपने इरादे की सूचना देने के लिए कम से कम चौदह दिनों का नोटिस देने के बाद और उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद।

(3) xx xx xx xx

(4) xx xx xx xx"

(4) यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि फर्म को निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए पहली बार पंजीकरण दिया गया है और इसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए, फर्म स्वचालित रूप से अधिनियम की खंड 184 की उप-खंड (7) के तहत एक पंजीकृत फर्म बनी रही क्योंकि फॉर्म-12 समय पर जमा किया जा रहा था। यहां तक कि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए भी, उक्त प्रपत्र समय पर प्रस्तुत किया गया था और यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि एन. आर. एम. के गठन या भागीदारों के शेयरों में कोई बदलाव हुआ था, यह सच है कि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के दौरान, फर्म अधिनियम की खंड 139 (2) और 142 (1) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा उसे जारी किए गए नोटिसों का पालन करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप आयकर अधिकारी के पास अधिनियम की खंड 144 के तहत सर्वोत्तम मूल्यांकन निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मेरी राय में, इस तरह का आदेश देते समय, आयकर अधिकारी के लिए अधिनियम की खंड 186 की उप-खंड (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना फर्म का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं था। चूंकि प्रपत्र-12 में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए अधिनियम की खंड 184 की उप-खंड (7) के प्रावधानों ने यह अनिवार्य कर दिया कि पहले के वर्षों में दिया गया पंजीकरण उस वर्ष के लिए भी प्रभावी रहेगा। आयकर अधिकारी को कोई विशिष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी और पंजीकरण जारी रखना स्वचालित था। अधिनियम की खंड 185 की उप-खंड (5) के प्रावधान वर्तमान जैसे मामले पर लागू नहीं होते हैं, जहां फर्म पहले से ही पंजीकृत थी और अधिनियम की खंड 184 (7) के तहत अपने पंजीकरण को स्वचालित रूप से जारी रखने का दावा कर रही थी। अधिनियम की खंड 185 (5) केवल तभी लागू होगी जब फर्म को फर्म के लिए पंजीकृत किया जाना है; इस समय और आयकर अधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करने के बाद पंजीकरण प्रदान करने वाला एक विशिष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है कि अधिनियम की खंड 184 की आवश्यकताओं का पालन किया जाता है। अपने पंजीकरण के बाद के सभी वर्षों के लिए, फर्म अपने पंजीकरण को स्वचालित रूप से जारी रखने का दावा कर सकती है बशर्ते वह समय पर फॉर्म-12 प्रस्तुत करे। किसी अन्य औपचारिकता से गुजरने की आवश्यकता नहीं है और आयकर अधिकारी उस प्रभाव के द्वारा कोई विशिष्ट आदेश पारित

किए बिना फर्म को मान्यता देना जारी रखने के द्वारा बाध्य है। दूसरे शब्दों में, यदि फॉर्म-12, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, क्रम में है, तो पंजीकरण की निरंतरता स्वचालित है और यदि आयकर अधिकारी किसी भी कारण से स्वचालित पंजीकरण को रद्द करना चाहता है, तो उसे अधिनियम की खंड 186 की उप-खंड (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी फर्म का मूल्यांकन करते समय, जिसमें वह पहली बार पंजीकरण की मांग कर रहा है, यदि आयकर अधिकारी संतुष्ट है कि फर्म ने कोई चूक की है जिसके लिए उसे पंजीकरण नहीं दिया जाना चाहिए, तो वह फर्म को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है और इसे एक अपंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इस शक्ति का प्रयोग वह अधिनियम की खंड 185 की उप-खंड (5) के तहत करेगा। अधिनियम की खंड 185 की उप-खंड (5) में "निर्धारण वर्ष के लिए फर्म को पंजीकृत करने से इनकार कर सकते हैं" शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि यह प्रावधान यह तब लागू होगा जब फर्म पहली बार पंजीकरण लॉट की मांग कर रही हो। यदि आयकर अधिकारी इस प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खुला था, तब भी जब फर्म पहले से ही पंजीकृत थी, तो अधिनियम की खंड 186 की उप-खंड (2) में उपयोग किए गए शब्द "या इसका पंजीकरण खंड 184 की उप-खंड (7) के तहत प्रभावी है या कोई भी निर्धारण वर्ष" निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार, एक बार पंजीकरण स्वीकृत हो जाने के बाद और किसी भी बाद के वर्ष के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें फॉर्म-12 प्रस्तुत किया गया है, आयकर अधिकारी के लिए अधिनियम की खंड 185 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खुला नहीं है और यदि पंजीकरण जारी रखना रद्द किया जाना है, तो अधिनियम की खंड 186 की उप-खंड (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह विचार कि मैं ले रहा हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले का समर्थन करता है, जिसे आयकर के अतिरिक्त आयुक्त बनाम राधा किशन बनवारी लाल<sup>2</sup> (2) के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

(5) तत्काल मामले में, फर्म को वर्ष में पहली बार पंजीकृत किया गया था और इसके बाद इसका पंजीकरण जारी रहा और संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए फर्म द्वारा समय पर आवश्यक घोषणा फॉर्म-12 जमा किए जाने के बाद, आयकर अधिकारी उस मूल्यांकन वर्ष के लिए अधिनियम की खंड 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन करते हुए, इसलिए, अधिनियम की खंड 186 (2) का सहारा लिए बिना पंजीकरण को रद्द नहीं कर सकता था। आयकर अधिकारी के साथ-साथ आयकर

आयुक्त का भी विवादित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और रद्द किए जाने के योग्य है।

- (6) विभाग की ओर से पेश हुए वकील ने सूरजमुल नागरमुल के मामले (उपरोक्त) में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले पर यह तर्क देने के लिए मजबूत भरोसा व्यक्त किया कि आयकर अधिकारी के लिए अधिनियम की खंड 185 (5) के तहत पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है, भले ही फर्म पहले से ही मूल्यांकन वर्ष 1977-78 के लिए पंजीकृत हो। वकील के अनुसार, राधा किशन बनवारी लाल के मामले (उपरोक्त) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार सही नहीं है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया जाना चाहिए। मुझे इस विवाद में कोई दम नजर नहीं आता। सूरजमुल नागरमुल के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश आयकर अधिनियम, 1922 की खंड 23 (4) और 26ए के प्रावधानों पर विचार कर रहे थे, जिसके तहत अधिनियम की खंड 184 की उप-खंड 7 में निहित प्रावधान के समान कोई प्रावधान नहीं था। 1922 के अधिनियम के तहत, एक फर्म को हर साल एक आवेदन दायर करके खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता थी, जबकि अब इसके तहत ऐसा नहीं है।

ऐसा अधिनियम जिसमें एक बार दिया गया पंजीकरण स्वतः जारी रहता है, बशर्ते कि निर्धारित समय के भीतर प्रपत्र-12 में अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करे। इस कारण से, कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

- (7) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और आयकर अधिकारी का आदेश जिस हद तक याचिकाकर्ता फर्म को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए एक अपंजीकृत फर्म के रूप में मानता है, उसी तरह आयुक्त का आदेश भी रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, यह आयकर अधिकारी के लिए कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने के लिए खुला होगा। दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।
-



अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़, हरियाणा